भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 947

उत्तर देने की तारीख-10/02/2025

अनुसंधान संस्कृति को प्रोत्साहन

†947. श्री थरानिवेंथन एम. एस.:
श्रीमती कृति देवी देबबर्मन:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश भर में अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और युवा शोधकर्ताओं के बीच अनुसंधान नवाचार को सहायता प्रदान करने के लिए कौन-कौन से विशेष उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) इस प्रकार की अनुसंधान संस्कृति के लिए अनुमानित निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त योजना के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित समय-सीमा, लक्षित लाभार्थियों और सतत् अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने में इसकी सफलता को मापने के लिए प्रमुख निष्पादन संकेतक (केपीआई) का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (घ): राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में उत्कृष्ट शिक्षा और विकास के लिए एक सह-आवश्यकता के रूप में उत्कृष्ट अनुसंधान की परिकल्पना की गई है। तदनुसार, देश में अनुसंधान संस्कृति के संवर्धन के लिए कई पहलें की गई हैं।

शिक्षा मंत्रालय का नवाचार प्रकोष्ठ शैक्षणिक संस्थानों में सामाजिक हित के लिए तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देता है। रचनात्मकता और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने वाले वातावरण को बढ़ावा देकर, सेल दीर्घकालिक वाणिज्यिक मॉडल के विकास की सुविधा प्रदान करता है। स्मार्ट इंडिया

हैकथॉन (एसआईएच), इंस्टीट्यूशनसंइनोवेशन काउंसिल (आईआईसी), कपिला (कलाम प्रोग्राम फॉर आईपी लिटरेसी एंड अवेयरनेस), इनोवेशन, डिजाइन एंड एंटरप्रेन्योरशिप (आईडीई) बूटकैंप और एआईसीटीई एमओई इन्वेस्टर नेटवर्क जैसी पहलों के माध्यम से, यह मुख्य उच्चतर शिक्षण संस्थानों (एचईआई) में नवाचार को एकीकृत करने का प्रयास करता है। इनोवेशन सेल विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी विभागों के साथ सहयोग करता है, यह सुनिश्चित करता है कि ये नवाचार वास्तविक दुनिया की चुनौतियों का समाधान करते हुए सामाजिक प्रगति में योगदान करते हैं।

देशभर में तेईस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) स्थापित किए गए हैं जो तकनीकी शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार में उत्कृष्टता के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रमुख संस्थान हैं। बजट 2025-26 में 2014 के बाद शुरू किए गए पांच आईआईटी में 6,500 और छात्रों को शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचे के निर्माण की परिकल्पना की गई है।

इसके अलावा, "आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उत्कृष्टता केंद्र" के संबंध में बजट घोषणा 2023-24 के पैरा 60 के अनुसरण में, सरकार ने स्वास्थ्य, दीर्घकालिक शहर और कृषि के क्षेत्रों में एक-एक; वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 की अवधि के लिए 990.00 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) में तीन उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की स्थापना को मंजूरी दी है; शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चौथे उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा भी बजट 2025-26 में की गई है।

देश के सात भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) भी पूर्व स्नातक और स्नातकोत्तर स्तरों पर गुणवत्तायुक्त विज्ञान शिक्षा प्रदान करने के लिए विज्ञान के अग्रणी क्षेत्रों में अनुसंधान करते हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआइएससी) बेंगलुरु उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान का एक प्रमुख संस्थान है।

बजट 2018-19 में घोषित प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप (पीएमआरएफ) योजना देश के विभिन्न उच्चतर शिक्षण संस्थानों में शोध की गुणवत्ता में सुधार के लिए बनाई गई है। वित्तीय सहायता, मान्यता और समृद्ध शोध वातावरण प्रदान करके, इस योजना का उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना, अंतर विषयक अनुसंधान को प्रोत्साहित करना और पीएचडी कार्यक्रमों की गुणवत्ता को बढ़ाना है। अब तक की स्थिति के अनुसार देश में विभिन्न पीएमआरएफ अनुदान संस्थानों

में पीएमआरएफ योजना के तहत **3688** शोध कर्ताओं को प्रवेश दिया गया है। इस योजना के तहत **31.01.2025** तक **1067** करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर) विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों और कॉलेजों में कार्यरत संकाय/विद्वानों के अनुसंधान को वित्तीय मदद करके भारत में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र का पोषण करती है। आईसीएसएसआर के पास विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में युवा अनुसंधानकर्ताओं तथा अनुसंधान संस्कृति एवं नवाचार को सहायता प्रदान करने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ अनुसंधान अध्येतावृत्तियां (डॉक्टोरल, पोस्ट-डॉक्टोरल और वरिष्ठ), अनुसंधान कार्यक्रम (अंतर विषयक बहु-विषयक/अंतर-संस्थागत), अनुसंधान परियोजनाएं और संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं, सेमिनारों/कार्यशालाओं, प्रकाशनों आदि जैसे कार्यकलापों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल हैं। वर्ष ***2024*** के दौरान, आईसीएसएसआर ने ***483*** डॉक्टरेट और ***273*** पोस्ट-डॉक्टरल फैलोशिप और ***33*** सीनियर फैलोशिप प्रदान की है। इसके अलावा, अपने प्रमुख मेजर और माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट्स के माध्यम से, आईसीएसएसआर विद्वानों को अनुसंधान करने के अवसर प्रदान करता है जो वास्तविक दुनिया की नीति और सामाजिक चुनौतियों में योगदान देता है। वित्त वर्ष ***2024-25*** के लिए ***250*** प्रमुख अनुसंधान परियोजनाएं और ***250*** लघु अनुसंधान परियोजनाएं आवंटित की गई हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने उच्चतर शिक्षा संस्थानों के भीतर अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित और मजबूत करने के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित करने के लिए "उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान और विकास प्रकोष्ठों की स्थापना के लिए दिशानिर्देश" तैयार किए हैं। यूजीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार, अब तक **1716** उच्चतर शिक्षा संस्थानों ने अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठों की स्थापना की है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विद्याथयों को उन्नत अध्ययन और अनुसंधान करने का अवसर प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेट-जूनियर अनुसंधान अध्येतावृत्ति योजना भी कार्यान्वित कर रहा है। वर्ष **2023-24** के दौरान यूजीसी द्वारा इस योजना के तहत **36050** लाभार्थियों को **1640.84** करोड़ रुपये की धनराशि वितरित की गई है।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) अपने अभिनव अनुसंधान, मजबूत मौलिक विज्ञान, उद्योग भागीदारी, उद्यमिता, रूपांतरणात्मक अनुसंधान, क्षमता निर्माण और नीति निर्माण के माध्यम से राष्ट्रीय जरूरतों को भी पूरा करती है। क्षमता निर्माण के अंतर्गत,

सीएसआईआर ने डॉक्टोरल और पोस्टडॉक्टोरल अध्येतावृत्ति, बाह्य अनुसंधान योजना और एमेरिटस वैज्ञानिक योजना जैसे विभिन्न उप-कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया है।

भारत वर्ष में अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी अवसंरचना (एफआईएसटी) कार्यक्रम के सुधार के लिए निधि और विश्वविद्यालय अनुसंधान और वैज्ञानिक उत्कृष्टता (पर्स) योजना भी कार्यान्वित कर रहा है।

इसके अलावा, गणितीय विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और पृथ्वी विज्ञान, स्वास्थ्य और कृषि सहित प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता के लिए उच्च स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना के लिए "अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन अधिनियम, 2023" अधिसूचित किया गया है। यह मानविकी और सामाजिक विज्ञान के वैज्ञानिक और तकनीकी समन्वय को बढ़ावा देना चाहता है। पांच वर्षों के लिए अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की कुल अनुमानित लागत 50,000 करोड़ रुपये है।

*****